जाती है और इसका कितना उत्पादन होता है और उसमें से आदिवासी क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसका समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशों में भी "रामतिल" की मांग है; यदि हां, तो इसके निर्यात के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है; और

(ङ) क्या "रामतिल" के निर्यात की सम्भावनाओं को देखते हुए इस फसल पर कोई अनुसंधान-कार्य किए जा रहे हैं ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) 1992-93 में मध्य प्रदेश राज्य में इसका अनुमानित क्षेत्र 2.08 लाख हैक्टेयर था तथा 34 हजार मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन हुआ था । लेकिन, आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र और उत्पादन का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं है ।

(ग) जी, नहीं, क्योंकि रामतिल को कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं किया गया है ।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब कभी विदेशों से रामतिल की मांग प्राप्त होती है तो इसका निर्यात किया जाता है । भारत सरकार की वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार रामतिल का निर्यात राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ के माध्यम से किया जाता है ।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसका मुख्यालय जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में है के माध्यम से रामतिल पर अनुसंधान कर रहा है ।

Availability of Milk in the Country

2253. SHRI MURLIDAHR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of diverted milk to produce milk processd items;

(b) what is the per capita availability of milk in the country;

(c) how It compares with certain advanced countries; and

(d) the details of steps taken by Government to make available milk at cheaper rate to cliildem and women who are living below poverty line ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is estimated that nearly 50% of milk production in India is diver-led to produce processed items, such as ghee, milk powder, butter, khoa, paneer/chana/ cheese, curd/dahi, and sweets.

(b) The per capita availability of milk in the country is 64.2 Kg. per head per annum (1991).

(c) The per capita availability of milk in certain advanced countries is as under (1991):

UK	— 260 Kg. Per annum
USA	— 268 Kg. per annum
Japan	— 66 Kg. per annum
Germany (FR)	— 369 Kg. per annum

(d) Government has recently promulgated Milk and Milk Product Order, 1992 on 9th June,
1992 under the Essential Commodities Act, (10
of 1955) with a view to maintain and increase supply of liquid milk of the desired quality in the interest of the general public. This Order extends to the whole of India.

राष्ट्रीय कृषि-विस्तार परियोजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को शामिल किया जाना

2254. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि-विस्तार परियोजना I और 3 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को शामिल किया था;

(ख) यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं और

(ग) गत वर्ष जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सका है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी, हाँ । उत्तर प्रदेश के 25 पूर्वी जिलों के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 में शामिल किया गया है ।

(ख) पूर्वी जिलों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(ग) परियोजना के तहत जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं; लेकिन 1992-93 तक के वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों और पूरी परियोजना की समग्र उपलब्धियों को विवरण-II में दर्शाया गया है ।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 में शामिल पूर्वी जिलों के नाम

1. वाराणसी 14. बहराइच

2. जौनपुर
3. गाजीपुर
4. बलिया
5. गोरखपुर
6. देवरिया
7. बस्ती
8. आजमगढ़
9. लखनऊ
10. उन्नाव
11. रायबरेली
12. सीतापुर
13. फैजाबाद
15. सुल्तानपुर
16. प्रतापगढ़
17. सिद्धार्थनगर
18. सोनभद्र
19. मऊ
20. महाराजगंज
21. गोण्डा
22. सीतापुर
23. मिर्जापुर
24. बारा बंकी
25. हरदोई

विवरण-II

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 के अंतर्गत समग्र प्रगति

1. वित्तीय

(रुपए मिलियन में)

परियोजना	परियोजना लागत	व्यय (मार्च, 93 तक)	ऋण वितरण (मार्च, 93 तक)
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	1151.80	889.59	625.60

2. वास्तविक

परियोजना	मदें	लक्ष्य	उपलब्धियां (मार्च, 93 तक)
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	1) कर्मचारी	5657	4643
	2) निर्माण कार्य	1954	896
	3) वाहन	175	156

राष्ट्रीय कृषि परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

2255. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान क्या कार्य किया गया है और उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों (25 जिले) में एक तथा पश्चिमी जिलों (30 जिले) में दूसरी विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना चल रही है । राज्यों को विश्व बैंक की सहायता सीधे न दी जाकर प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाती है । बहरहाल, परियोजना को बजटीय समर्थन देने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा कुछ अग्रिम केन्द्रीय सहायता दी जाती है । राज्य को दी गई अग्रिम केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) इस परियोजना के तहत जिलावार लक्ष्य तैयार नहीं किए जाते हैं, फिर भी 1991-92 और 1992-93 को सम्मिलित करते हुए संचित वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों को विवरण-II में दर्शाया गया है ।

विवरण-I (लाख रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई अग्रिम केन्द्रीय सहायता			
		90-91	91-92	92-93	योग
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (पश्चिमी जिले)	100	100	—	200
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (पूर्वी जिले)	50	200*	300	550
		150	300	300	750

*पनधारा परियोजनाओं को दी गई सहायता भी शामिल है ।

विवरण-II

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजनाओं के तहत होने वाली संचित प्रगति—उत्तर प्रदेश

1. वित्तीय (मिलियन रुपए में)

परियोजना	परियोजना लागत	व्यय (मार्च, 93 के अंत तक)	वितरित ऋण (मार्च, 93 के अंत तक)
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (पश्चिमी जिले)	1219.07	676.83	504.79